

सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-16 22 अगस्त से 5 सितम्बर, 2017

मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष

कुल पृष्ठ 8

मूल्य : 2 रुपये

कॉमरेड शिवदास घोष के 41वें स्मृति दिवस पर उनकी देदीप्यमान शिक्षाओं को देशभर में किया गया याद

हम 5 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन हमारे प्रिय नेता शिक्षक और पथ-प्रदर्शक, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव और इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार कॉमरेड शिवदास घोष अपनी भरी जवानी में 1976 में गुजर गये थे। यह दिन हम उनको खोने के अपने दुख-दर्द और कटु अहसास को व्यक्त करने के लिए ही नहीं मनाते हैं, यह तो सालों साल से घटने का नाम नहीं ले रहा बल्कि इस दिन को मानव जाति की मुक्ति के लिए, इस देश के मेहनतकश लोगों के क्रान्तिकारी संघर्ष में तहदिल से जुट जाने के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लेने के दिन के तौर पर मनाते हैं। यह स्मृति दिवस ऐसे समय आया है जब महान नवम्बर क्रान्ति का शताब्दी वर्ष चल रहा है, देशभर में वर्ग संघर्षों और जन आन्दोलनों को गठित करने में गहरी प्रेरणा के स्रोत के तौर पर काम करने वाली महान नवम्बर क्रान्ति मनाने और उससे सीख लेने के लिए वर्ष-व्यापी कार्यक्रम चल रहा है।

महान मार्क्सवादी चिंतनकार कॉमरेड शिवदास घोष जो भारत की सरजमीं पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद की

शिक्षाएं, महान नवम्बर क्रान्ति की शिक्षाएं सही मायने में सजीव रूप में लाये थे। विचार-विश्लेषण के वैज्ञानिक तरीके मार्क्सवाद-लेनिनवाद को सचेत रूप से और लगातार हर क्षेत्र में लागू करते हुए उन्होंने भारत की सरजमीं पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में लागू किया, वे इसे विशेषीकृत, विस्तार से व्याख्यायित, समृद्ध करते हुए इसकी समझदारी को नयी बुलन्दियों पर ले गये। इस प्रक्रिया में वे कम्युनिस्ट चरित्र और संस्कृति की उदात्त बुलन्दियों के जीते-जागते प्रतीक उभरे। क्रान्तिकारी संघर्षों को सर्वहारा संस्कृति और नीति-नैतिकता से लैस करने के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान करते हुए उन्होंने सिखाया कि मार्क्सवाद के उन्नत नैतिक-सांस्कृतिक और सौन्दर्यबोधात्मक स्तर में ही इसका सार निहित है। इस उन्नत नीति-नैतिकता के बिना सर्वहारा वर्ग अपनी वांछित मंजिल तक कभी नहीं पहुँच सकेगा।

जहाँ नवम्बर क्रान्ति दुनियाभर के शोषित-पीड़ित, दबे-पिसे लोगों के लिए आशा और गहरी प्रेरणा की प्रकाश स्तम्भ रही और आज भी है, वहीं पूँजीपति वर्ग के लिए ये आज भी एक बुरा सपना बना हुई है। विश्व

साम्राज्यवाद-पूँजीवाद से शह पाकर संशोधनवादियों द्वारा साजिश रच कर की गई प्रतिक्रान्ति से समाजवादी देशों के ढह जाने के बाद भी पूँजीपति क्रान्ति की भयग्रन्थी से कभी निजात नहीं पा सके। क्योंकि चाहे वे स्वीकार करें या न करें पूँजीवाद का तबाही मचाने वाला और कभी हल न होने वाला संकट जनजीवन में कहर ढा रहा है, भीषण पूँजीवादी शोषण के दमघोंटू शिकंजे को तोड़ने की चाह समाज में बढ़ रही है। अगर इन सताये हुए करोड़ों-करोड़ लोगों को उन्नत संस्कृति वाली विचारधारा मिल जाए जिसकी उन्हें अपनी मुक्ति के लिए जरूरत है और उसकी पकड़ हासिल कर लें तो वे इस गयी-गुजरी, सड़ी-गली, बेरहम शोषणकारी पूँजीवादी व्यवस्था की मौत की घंटी बजा सकते हैं। यही वजह है कि अपने कपटी साज्यों के अंग के तौर पर लच्छेदार भाषण, सदाचार के प्रवचन देते हुए शासक पूँजीपति वर्ग और सरकारी गद्दी पर बैठे उसके दलाल हर तरह की गन्दी और घटिया बातों को पनपा रहे हैं और सौन्दर्यबोधात्मक रुचि, नीति-नैतिकता और संस्कृति पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गोरखपुर हस्पताल में 70 बच्चों की हृदय विदारक मौत के दोषियों को सख्त सजा देने की एसयूसीआई (सी) ने की मांग

14 अगस्त, 2017 को एसयूसीआई (सी) के महामंत्री कॉमरेड प्रभास घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया:

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कथित तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई के अभाव में 5 दिनों के दौरान 70 बच्चों की हृदय विदारक मौतें, बीजेपी शासन में सरकारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की लचर हालत को पूरे भद्देपन के साथ उजागर करती हैं। यह आशंका है कि मौतों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यतः इन्सेफेलाइटिस के रोगियों का इलाज करने वाला यह हस्पताल यू.पी. के बीजेपी मुख्यस मंत्री के विधान सभा क्षेत्र में स्थित है और एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री 10 बिस्तर के आईसीयू और 6 बिस्तर की एक क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन करने गये थे तथा उस वार्ड का भी दौरा किया था जिसमें इस घटना के शिकार इन्सेफेलाइटिस से संक्रमित बच्चे दाखिल थे। जब भाण्ड या गोदी मीडिया उनके दौरे का गुणगान करते हुए दिखा रहा था कि जन-स्वास्थ्य के प्रति उनका कितना सरोकार है ठीक उसी समय पीड़ित बच्चों के सिर पर मौत मंडरा रही थी, कारण था कथित तौर पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेण्डरों की कमी हो जाना क्योंकि हस्पताल ने गैस सप्लाई एजेंसी के बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया था—एक ऐसा तथ्य जो हर सही सोच रखने वाले संवेदनशील व्यक्ति को हैरान-परेषान करता है कि कहीं भी राज्य हो या केन्द्र कोई संवेदनशील सभ्य सरकार है क्या? यह दर्दनाक हादसा एकबार पुनः दर्शाता है कि जहाँ बीजेपी और इसकी सरकारें गायों को बचाने में इतनी दिलचस्पी रखती हैं वहीं बच्चों समेत आम लोगों के जीवन से उनका कोई सरोकार नहीं है।

शोक संतप्त परिवारों की अपूर्णीय क्षति को साझा करते हुए हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और यह भी मांग करते हैं कि इस जघन्य अपराध के तमाम दोषियों को सख्त सजा दी जाये।

मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान : मजदूर-विरोधी नीतियां उलटवाने के लिए मिल कर लड़ें 9-10-11 नवम्बर को मजदूर डालेंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर पड़ाव



दिल्ली: तालकटोरा स्टेडियम में मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉ. शंकर साहा

नई दिल्ली : 8 अगस्त 2017 को मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में हुआ। औद्योगिक और सर्विस सेक्टर दोनों की दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने स्वतंत्र राष्ट्रीय मजदूर फेडरेशनों के साथ संयुक्त रूप से सम्मेलन का आह्वान किया था। सम्मेलन के अध्यक्षमण्डल में अशोक सिंह (इंटक), रामेन्द्रकुमार (एटक), एसएन पाठक (एचएमएस), एच. हेमलता (सीटू), सत्यवान (एआईयूटीयूसी), लता (सेवा), उदय भट्ट (एक्कटू),

शत्रुजीत सिंह (यूटीयूसी), वी. सुब्रमण्यम (एलपीएफ) शामिल थे।

सम्मेलन को जी. संजीवा रैडी (इंटक), अमरजीत कौर (एटक), हरभजन सिंह सिद्धू (एचएमएस), तपन सेन (सीटू), शंकर साहा (एआईयूटीयूसी), मनाली (सेवा), राजीव डिमरी (एक्कटू), एस रामचन्द्रन (यूटीयूसी) व एम. शनमुगम (एलपीएफ) आदि वक्ताओं ने सम्बोधित किया। सम्मेलन में नरेन्द्र मोदी सरकार

(शेष पृष्ठ 7 पर)

5 अगस्त ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अनगिनत हमले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और अपराधों की तो बात ही क्या करें जो उनका पूँजीवादी शासन पैदा करता है, यहां तक कि अंधता और रुढ़िवाद को भी हवा दे रहे हैं, इस पृष्ठ भूमि में हम कॉमरेड शिवदास घोष का स्मृति दिवस मना रहे हैं। हम कॉमरेड शिवदास घोष की सीखों का अध्ययन मनन करने और उन्हें आत्मसात करने और उनके विचारों को जनता में फैलाने के संघर्ष में अपने आप को और भी ज्यादा जोश खरोश और निष्ठा के साथ खुद को सलंगन करने का संकल्प लेते हैं। इसके साथ ही जन आन्दोलनों को गठित करने और इन्हें इनकी अन्तिम मंजिल और क्रान्तिकारी संघर्ष की ओर आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करने का भी संकल्प लेते हैं।

देशभर में आयोजित स्मृति सभाओं के अब तक प्राप्त समाचार नीचे दे रहे हैं। हर जगह स्मृति सभाओं की शुरूआत कॉमरेड शिवदास घोष की तस्वीर पर माल्यार्पण, उन पर रचित गीत गायन से हुई और समापन अन्तर्राष्ट्रीय गान से हुआ। कुछ जगह किशोर कम्युनिस्ट विंग, कोम्सोमोल के वालिन्टरों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

दिल्ली : इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महामंत्री, हमारे नेता, शिक्षक, पथ प्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष के 41वें स्मृति दिवस पर पार्टी की दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा 6 अगस्त 2017 को एन.डी. तिवारी भवन आईटीओ दिल्ली में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के मुख्य वक्ता रहे पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य तथा एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा। सभा की अध्यक्षता दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव प्राण शर्मा ने की। दिल्ली के विभिन्न इलाकों और तबकों से सैकड़ों लोगों ने सभा में शिरकत की।

कॉमरेड शंकर साहा ने बर्बर पूँजीवादी शोषण की वजह से लोग जिस बड़ी भारी कठिनाई से रूबरू हैं उसकी तरफ श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि जनता का दुश्मन अर्थात् भारतीय पूँजीपति वर्ग और उसके राजसत्ता रूपी तंत्र का जहां हमें बखूबी पता है वहीं हमें मजदूर वर्ग के अन्दर जो दुश्मन है उसे भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके खिलाफ जीवन के हर क्षेत्र में हमें सतत संघर्ष चलाना होगा यह दुश्मन है 'व्यक्तिवाद' जो लगातार मजदूर वर्ग की ताकत को चुन की तरह खाये जा रहा है। कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया था कि पहले अच्छे कम्युनिस्ट होने का पैमाना यह होता था कि सामाजिक हित के आगे व्यक्तिगत हित को गौण समझना लेकिन अब पूँजीवाद की मरणासन्न और हासकारी परिस्थितियों में जब व्यक्तिवाद और गहरी जड़ जमा चुका है और जटिल हो चुका है, कम्युनिस्टों को जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक हित अर्थात् पार्टी और क्रान्ति के हित के साथ अपने व्यक्तिगत हित को एकाकार कर देना होगा। केवल तभी कोई सही कम्युनिस्ट चरित्र हासिल कर सकता है जो समाजवादी क्रान्ति के हित से मेल खाता हुआ होगा। एक समय की बड़ी-बड़ी वामपंथी पार्टियां जैसे कि आरएसपी, आरसीपीआई, वर्कर्स पार्टी,



रोहतक : सभा को संबोधित करते हुए कॉ. शंकर साहा

बोलशेविक पार्टी, ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक आदि या तो परिदृश्य से गायब हो चुकी हैं या केवल उनका साइन बोर्ड बचा है। सीपीआई-सीपीएम जो एक समय कांग्रेस के बाद दूसरे नम्बर की पार्टियां थी आज बुर्जुआ पार्टियों की मदद से अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिए संघर्षरत हैं, जबकि एसयूसीआई (सी) जो आजादी के बाद अस्तित्व में आई अब देश के 23 राज्यों में इसका संगठन तेजी के साथ फैलता जा रहा है। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और हमदर्दों से अपील की कि वे सब अपनी कठिनाइयों व सीमाबद्धताओं से उभरें और पार्टी को मजबूत करें।

रोहतक (हरियाणा) : एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) ने अपने संस्थापक महासचिव, भारत की भावी समाजवादी क्रान्ति के पथ-प्रदर्शक व महान मार्क्सवादी विचारक कॉमरेड शिवदास घोष की 41वीं बरसी पर उनकी सीखों व जीवन चरित्र को याद किया। 5 अगस्त को प्रदेश भर से पार्टी के नेता-कार्यकर्ता आज छोट्टराम सभागार में इकट्ठे हुए और उन्हें तहेदिल से श्रद्धांजलि दी।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य एवं नामी श्रमिक नेता शंकर साहा ने जनजीवन की वर्तमान समस्याओं को लेकर देश-प्रदेश में एक जोरदार जनान्दोलन की उठती लहर को सही दिशा प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि महान नेता कामरेड शिवदास घोष के वैज्ञानिक चिंतन के बल पर खुद को सक्षम व योग्य बनायें और अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत कर जनता में एक नये विश्वास व भरोसे को पैदा करें। उन्होंने सचेत किया कि पूँजीपतियों के धन-बल से आजादी के बाद नये शासकों ने इस भरोसे को चूर-चूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूँजीवादी शासन-व्यवस्था का सबसे खतरनाक हमला इंसान को मानवीय मूल्यबोधों व उन्नत संस्कृति से रीता कर उन्हें यन्त्रनुमा रोबोट सरीखा खोखला जीव बनाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय नवजागरण के महान अग्रदूतों व आजादी आन्दोलन के महान सेनानियों-क्रान्तिकारियों ने देशवासियों में जिस विश्वास को पैदा किया था, उसे आज नये सिरे से बहाल करना होगा। केवल तभी वर्तमान में हर तरह के शोषण-उत्पीड़न को हटा फेंकने वाली क्रान्ति को सफल कर देश में समाजवादी जनतंत्र कायम किया जा सकता है। कॉमरेड शिवदास घोष का चिंतन समाजवाद

के इस महान आदर्श को साकार करने में शोषित जनता का मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि भगतसिंह से लेकर नेताजी सुभाषचंद्र बोस तक, प्रेमचंद-शरतचन्द्र-मेघनाथ साहा-आइन्सटीन सभी ने समाजवाद की सफलता में मानव जाति के भविष्य की कामना की थी।

शंकर साहा ने कहा कि कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सभी सरकारों ने हमेशा जनतान्त्रिक सोच व प्रगतिशील ताकतों को समाप्त करना चाहा है। आज खुल्लमखुल्ला युद्ध-पिपासु साम्राज्यवाद से गठजोड़ किया जा रहा है। इससे हालात भयावह बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में शिवदास घोष के अनुयायियों का दायित्व है कि वे मजदूर किसान, छात्र-युवा, महिलाओं समेत शोषित-उत्पीड़ितों की एकता व नये भाइचारे को सुदृढ़ करने में जी-जान से जुटें। इसी में क्रान्तिकारियों का अस्तित्व है। यही कॉमरेड शिवदास घोष को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

स्मृति सभा की अध्यक्षता पार्टी के हरियाणा राज्य सचिव कॉ. सत्यवान ने की। मंच का संचालन कॉ. अनूप सिंह मातनहेल ने किया।

पटना (बिहार) : "आज देश के गरीब, शोषित-पीड़ित आम आवाज आर्थिक संकट की गिरफ्त में है। बेलगाम महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी जंगल की आग की तरह फैल रही है। सम्पूर्ण पूँजीपति वर्ग की मदद से आरएसएस-बीजेपी समेत संघ परिवार का खतरनाक उभार हो रहा है।" उक्त बातें आज एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के तत्वावधान में पार्टी संस्थापक महासचिव तथा इस युग के प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक व दार्शनिक शिवदास घोष के 41वें स्मृति दिवस पर 6 अगस्त को स्थानीय आईएमए हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय सभा में मुख्य वक्ता पार्टी के झारखण्ड राज्य सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति ने कही। उन्होंने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बर्बर हमले के अपने प्रमुख एजेण्डे को लागू करने के जरिए संघ परिवार परिकल्पित तौर पर देश में फासीवादी शासन लागू करने में मशगूल है। साथ ही साम्प्रदायिकता सौहार्द पर खतरा मंडरा रहा है। इसी क्रम में संविधान में वर्णित सार्वभौमिक मानवाधिकारों व मौलिक अधिकारों, जिनकी बुर्जुआ पार्टियां डींग हांकी हैं, को पैरों तले रौंदा जा रहा है। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि अन्य राजनैतिक पार्टियां इन घोर साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ किसी तरह के प्रतिरोधात्मक आन्दोलन निर्मित करने के मूड में नहीं हैं, वरन् उन्होंने स्पष्ट तौर पर किसी तरह के टकराव में नहीं जाने का रास्ता अपनाया है। उन्होंने आगे कहा कि देश में एकाधिकारी पूँजीपति अपने वर्गीय मंसूबों को पूरा करते हुए गौरवपूर्ण साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की परम्परा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका की रहनुमाई में एकाधिकारी पूँजीवादी, साम्राज्यवादी ताकतें अन्यायपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं। इतना ही नहीं, ये शैतानी ताकतें दुनिया भर में अपना वर्चस्व कायम करने के इरादे से विभिन्न देशों में एक के बाद एक युद्ध छेड़ रही हैं। कॉ. समाजपति ने बताया कि आम आवाज के जीवन में व्याप्त इन तमाम परेशानियों और समस्याओं की जड़ देश में शोषण और मुनाफे पर आधारित मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था है।



दिल्ली : सभा को संबोधित करते हुए कॉ. शंकर साहा

(शेष पृष्ठ 4 पर)

गुरुग्राम मण्डल के किसानों का विरोध प्रदर्शन

गुड़गांव : 16 अगस्त 2017, आज ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के आह्वान पर जिला रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ व गुरुग्राम के किसानों व खेत मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन किया। किसान कमला नेहरु पार्क में इकट्ठे हुए और शहर में जोरदार नारे लगाते हुए प्रदर्शन करके कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। वहां पर किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री, हरियाणा को सौंपा। प्रदर्शन की अगुवाई संगठन के प्रदेश अध्यक्ष काँ. अनूपसिंह मातनहेल, प्रदेश सचिव काँ. जयकरण व उपप्रधान काँ. विजय कुमार ने की।

रेवाड़ी के जिला सचिव काँ. रामकुमार ने ज्ञापन को पढ़कर सुनाया जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों के लाभकारी दाम देने जो लागत मूल्य से 50 प्रतिशत ज्यादा हों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्राइवेट कंपनियों को बाहर कर इसे किसान-हितैषी बनाने, सभी किसानों के कर्ज खत्म करने, बुढ़ापा पेंशन 5000 रुपये महीना करने, मनरेगा स्कीम प्रभावी ढंग से लागू करके किसानों व खेत मजदूरों को पूरा साल काम देने व दैनिक मजदूरी 600 रुपये करने, आवारा पशुओं का स्थायी प्रबंध करने की मांग उठाई गई।

प्रदेश अध्यक्ष काँ. अनूपसिंह ने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार फसलों की लागत का 50 प्रतिशत लाभ देने का वादा किया था। परन्तु सत्ता में आने के बाद इससे मुकर गई। सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना बढ़ाने की बात बार-बार कर रही है। प्रधानमंत्री



फसल बीमा योजना में निजी कम्पनियों को आधिपत्य देकर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। परन्तु किसानों को इसका लाभ मिलने की बजाए उल्टा नुकसान हो रहा है। प्रदेश सचिव काँ. जयकरण ने कहा कि आज खेती-बाड़ी घाटे का सौदा हो गई है। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण, डीजल आदि कृषि उपयोगी चीजों के दाम लगातार बढ़ने से और फसलों के लाभकारी दाम न मिलने से किसान कर्ज के बोझ से परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार कारपोरेट घरानों का खरबों रुपये बट्टे खाते डाल चुकी है। परन्तु किसानों के कर्जे माफ करने से साफ इनकार कर रही है। वस्तु सेवा कर (जीएसटी) जैसे कानून से खेती में प्रयोग होने वाले औजार व अन्य सामान और भी महंगे हो गए हैं।

प्रदर्शन को सचिव काँ. रामकुमार, बलबीर, प्रधान जिला महेन्द्रगढ़, कैप्टन जयनारायण, संयोजक जिला गुरुग्राम ने भी सम्बोधित किया।

दिल्ली आंगनवाड़ी कर्मियों के संघर्ष की जीत

दिल्ली आंगनवाड़ी एम्पलाइज यूनियन, एआईयूटीयूसी के मार्गदर्शन में दिल्ली की आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स की मांगों को लेकर लम्बे अर्से से संघर्षरत है। यूनियन ने 1 मार्च 2017 को भी मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई थी। मांग की थी उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाये और इसी के अनुरूप पूर्ण वेतन व अन्य लाभ दिये जाएं। उस समय ही यूनियन ने सरकार को चेताया था कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो वे हड़ताल के लिए विवश होंगे। अतः 4 जुलाई से दिल्ली में आंगनवाड़ी एम्पलाइज ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल धीरे-धीरे तेज होती गयी। बवाना के बरनाला गांव में दिल्ली आंगनवाड़ी एम्पलाइज यूनियन की विशाल सभा में आप पार्टी के नेता आशुतोष ने घोषणा की कि आप सरकार शीघ्र ही आपके मानदेय को दुगुना कर देगी। उन्होंने हड़ताल वापस लेने की अपील की। मगर यूनियन ने कहा कि जब तक सरकार इसका नोटिफिकेशन नहीं कर देगी हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। अतः 22 जुलाई को दिल्ली सरकार की कैबिनेट को मानदेय बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा।

इसकी घोषणा करते हुए दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ा कर 10170 रुपये व हेल्पर का 2500 रुपये से बढ़ा कर 5089 रुपये कर दिया है। इसके अलावा मोबाइल खर्च के रूप में वर्कर को 500 रु. व हेल्पर को 250 रु. देने की घोषणा की गई। यूनियन ने सरकार से इसकी लिखित प्रति मांगी और पुछा कि वह इसे कब से लागू करेगी।

27 जुलाई को पुनः आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर श्री आशुतोष ने आंगनवाड़ी एम्पलाइज यूनियन की सभा में वादा किया कि वे इसकी प्रति जल्द से जल्द यूनियन को दे देंगे व उप राज्यपाल की इजाजत जो जल्द ही मिल जाएगी, के बाद इसे लागू कर देंगे। सरकार ने अपने निर्णय की एक प्रति 4 अगस्त को यूनियन को दे दी है।

आंगनवाड़ी एम्पलाइज के द्वारा इस जुझारू आन्दोलन की जीत पर यूनियन के सलाहकार रामकरण, अध्यक्ष एम चौरसिया, एआईयूटीयूसी के दिल्ली राज्य अध्यक्ष हरीश आंगनवाड़ी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इण्डिया (एफी) के राष्ट्रीय सलाहकार काँ. अचिंत्य सिंहा व राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चहल ने हार्दिक बधाई दी है व अभिनन्दन किया है। उन्होंने कहा है कि इस आन्दोलन को हमें और भी ऊंचाई पर ले जाना है ताकि सरकार मान ले की आंगनवाड़ी एम्पलाइज सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें उन्हीं की तरह से वेतन व हक दिये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आंगनवाड़ी एम्पलाइज का आन्दोलन व उनकी जीत देशभर की आंगनवाड़ी कर्मियों में आन्दोलन की प्रेरणा पैदा करेगी।

‘पानी की किल्लत दूर करो’ की उठी मांग

जयपुर (राजस्थान) : लुनियावास, जयपुर में पानी की किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन कर एआईडीवाईओ-एआईएमएसएस ने 4 अगस्त को ज्ञापन सौंपा। संगठनों के कार्यालय से लुणियावास स्टैंड तक हुए इस प्रदर्शन में इलाके के लोग, खासकर महिलाएं पूरे जोश-खरोश के साथ काफी संख्या में शामिल हुईं। वहां हुई सभा को एआईडीवाईओ राजस्थान के प्रभारी काँ. कुलदीप सिंह, एआईएमएसएस राजस्थान की ओर से काँ. धीरू सिंह ने सम्बोधित किया।

इसके बाद 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल जल भवन, जयपुर गया और चीफ इंजीनियर के निजी सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीने के पानी का इन्तजाम जल्द से जल्द करने की मांग की गई।



लुनियावास

दिल्ली एम्बुलेन्स कर्मियों की शानदार जीत

दिल्ली एम्बुलेन्स सर्विस (कैट्स) के 1200 अनुबन्धित कर्मचारी लम्बे समय से सरकार, प्रशासन व ठेकेदार कम्पनी के शोषण व अन्याय से परेशान थे। उन्होंने इससे लड़ने के लिए कैट्स एम्बुलेन्स स्टाफ यूनियन का गठन किया और एआईयूटीयूसी के नेतृत्व में अपने आन्दोलन का संचालन किया। आन्दोलन के पहले चरण में सरकार को ईएसआई और भविष्य निधि (पीएफ) सुविधा प्रदान करने के लिए विवस किया। आन्दोलन के दूसरे चरण में आवज उठाई गई की सरकार 12 घण्टे की जगह 8 घण्टे का कार्य दिवस बनाये। कैज्यूअल लीव, अर्न्ड लीव सहित सभी तरह की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश दे। अतिरिक्त काम का अतिरिक्त भुगतान करे। कर्मचारियों का बिना वजह से दूर-दराज क्षेत्रों में स्थानान्तरण बन्द करे। स्थानान्तरण की पारदर्शी नीति बनाई जाए। पूर्व समझौते के अनुसार 5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ते को समय पर वेतन में जोड़ा जाए। इन मांगों को लेकर यूनियन ने 2 अगस्त 2017 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिया। नोटिस मिलने के बाद से ही ठेकेदार कम्पनी व सरकार में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों की एकजुटता, यूनियन का सुदृढ़ निर्णय व एआईयूटीयूसी के सही मार्गदर्शन के सामने सरकार, प्रशासन व ठेकेदार कम्पनी को झुकना पड़ा और 9 अगस्त को देर शाम तक चली बैठक में अन्ततः उन्हें कर्मचारियों की लगभग सभी मांगों को मानने का लिखित समझौता करना पड़ा।

इस महत्वपूर्ण जीत पर एआईयूटीयूसी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरीश त्यागी, उपाध्यक्ष का. विरेन्द्र सिंह दहिया, एनपीएचए की दिल्ली एपेक्श कमेटी के महासचिव काँ. एस.एस. नेगी तथा विजय कुमार ने क्रान्तिकारी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कैट्स कर्मचारियों की मजबूत एकता, कुशल नेतृत्व व सही मार्गदर्शन की उपलब्धि है। यह जीत न केवल दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मचारियों को बल्कि अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी।

एसयूसीआई (सी) का तीसरा जौनपुर जिला सम्मेलन

सोशललिस्ट यूनियटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का तृतीय जौनपुर जिला सम्मेलन 23 जुलाई को सल्तनत बहादुर पी.जी. कॉलेज बदलापुर में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन शुरू होने के पहले लाल झण्डा फहराया गया और शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया गया। कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत प्रस्तुत करके सम्मेलन की शुरुआत की गयी। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉमरेड जगदीशचन्द्र और संचालन काँ. जगन्नाथ वर्मा ने किया। जिला सचिव रिपोर्ट की प्रस्तुति काँ. जगदीशचन्द्र अस्थाना ने की। प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुमोदन किया। सम्मेलन को एसयूसीआई(सी), उ.प्र. राज्य सचिव कॉमरेड बी.एन. सिंह ने और पार्टी के उ. प्र. सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड स्वप्न चटर्जी ने सम्बोधित किया। इसके बाद सर्वसम्मति से 16 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें काँ. रविशंकर मौर्य को जिला सचिव चुना गया।

अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय गान गाया गया और जोरदार नारों के साथ सम्मेलन सम्पन्न हुआ।



जौनपुर : सम्मेलन को संबोधित करते हुए काँ. बी.एन. सिंह

5 अगस्त ...

(पृष्ठ 2 का शेष)



पटना : सभा को संबोधित करते हुए डॉ. रबिन समाजपति

स्मृति सभा की अध्यक्षता करते हुए एसयूसीआई (सी) बिहार के राज्य सचिव अरूण कुमार ने सर्वहारा के महान नेता शिवदास घोष के जीवन-संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश की एकमात्र सही साम्यवादी पार्टी एसयूसीआई (सी) के निर्माण का संघर्ष ही शिवदास घोष का जीवन संघर्ष है। उन्होंने कहा कि अपने देश सहित विश्व साम्राज्यवाद-पूँजीवाद आज अभूतपूर्व संकटों में उबल रहा है। वहीं जनता प्रतिवाद, प्रतिरोध और संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ रही है। वह इस शोषणमूलक निजाम का खात्मा चाहती है। अतएव देश में क्रान्ति की वास्तविक स्थिति मौजूद है। ऐसे में आवश्यक ताकत के साथ मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त के आधार पर मजदूर वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी का नेतृत्वकारी भूमिका में आना आज वक्त का तकाजा है, जो वास्तविक जनमुक्ति के लिए पूँजीवाद विरोधी समाजवादी क्रान्ति को सफल करेगी। डॉ. सिंह ने कहा आज के जमाने में मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सर्वोन्नत समझ शिवदास घोष के विचारों को जीवन में उतारकर उच्च सैद्धान्तिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्तर हासिल करने का दृढ़ संकल्प लेना ही सर्वहारा के इस महान नेता के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी।

इस मौके पर पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्यगण भी मंच पर मौजूद थे।

बंगलौर (कर्नाटक)

“मजदूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग के बीच संघर्ष एक वर्ग युद्ध है। जैसे हर युद्ध में जीत-हार होती है, वैसे ही इस वर्ग युद्ध में भी है। इसी तरह समाजवाद जो एक विश्व शक्ति के तौर पर पिछली सदी में दुनिया के एक तिहाई हिस्से में कायम हुआ था, सदी के अन्त में उल्टाव का शिकार हुआ लेकिन यह अस्थायी उल्टाव है” यह बात बंगलौर के एससीएम हाल में एसयूसीआई(सी) के दिवंगत संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष के 41वें स्मृति दिवस पर 5 अगस्त को आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड के. राधाकृष्ण ने अपने भाषण में कही। साम्यवादी आन्दोलन में जो समस्याएं थी उनको कैसे बहुत पहले ही 1956 में कॉमरेड शिवदास घोष ने बखूबी समझ लिया था, इस पर विस्तार से रोशनी डालते हुए डॉ. राधाकृष्ण ने कहा, “डॉ. शिवदास घोष ने मार्क्सवाद के विज्ञान के आधार पर स्पष्ट व्याख्या करके बताया था कि समाजवाद जब अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब भी साम्यवादी दुनिया में क्या चल रहा था। समाजवादी व्यवस्था के ढहने की ओर ले जाने वाले कारणों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कॉमरेड शिवदास घोष ने शानदार ढंग से दिखाया था कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टियों में अँथोरिटी

बोध को अँथोरिटेरिनिज्म (गुरुवाद) की अंध भावना के साथ गडमड कर दिया गया था। उन्होंने नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच यांत्रिक सम्बन्ध की बजाय द्वन्द्वत्मक सम्बन्ध कायम करने की जरूरत पर बल दिया था। डॉ. शिवदास घोष ने स्तालिन को पूरा मान-सम्मान देते हुए साथ-साथ अन्तर्निहित कमजोरी को समझने में स्तालिन की सीमाबद्धियों की भी आलोचना की थी जो गलत अँथोरिटी बोध के व्यवहार के चलते साम्यवादी दुनिया में फैलती जा रही थी।

फासीवाद के खतरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “फासीवाद लाने के लिए हिटलर द्वारा समझाने-बुझाने और दमन करने के दोनों दांवपेंच अपनाये गये थे। फासीवाद विज्ञान के तकनीकी पहलू और अध्यात्मवाद का अजीबोगरीब सम्मिश्रण है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज वही दांवपेंच अपनाये जा रहे हैं। हिटलर के सत्ता-संघर्ष में उसकी मदद कुछ नकली कम्युनिस्ट पार्टियों ने की थी जिनके नेताओं को लेनिन ने ‘लेबर अरिस्टोक्रेट्स’ करार दिया था। ये ‘लेबर अरिस्टोक्रेट्स’ दुनिया भर में आज ट्रेड यूनियन आन्दोलनों और साम्यवादी आन्दोलन में अवसरवाद ला रहे हैं। हमें समूचे मजदूर आन्दोलन को इस अवसरवाद से छुटकारा दिलाना होगा जो बिना किसी संघर्ष या कुर्बानी के ही आसानी से कुछ पाना चाहते हैं। वे महज आर्थिक मांगों पर ही केन्द्रित कर रहे हैं और मजदूरों की राजनैतिक चेतना को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष को तिलांजलि दे रहे रहे हैं। उसी तरह सरकार ने भी मोटी तन्खाह-भत्ते देकर श्रमिकों के एक तबके को भी खरीद लिया है और इस प्रकार समझाने-बहलाने की नीति जारी रख रही है। इसके साथ ही वह किसी आन्दोलन को बर्दाश्त नहीं करती है और उसे दबाने के लिए टूट पड़ती है। इस संकट की घड़ी में हम सब को दुर्गुने जोश-खरोश के साथ काम करने का संकल्प लेने की जरूरत है ताकि हमारे सामने जो गतिरोध है, उसे हम तोड़ सकें।”

मार्क्सवाद के विज्ञान की अहमियत पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “किसी के साथ भविष्य में क्या होता है यह जानना आदमी के लिए न केवल उत्सुकता का विषय है, बल्कि जरूरत का मामला भी है। उसी से इतिहास में विज्ञान का ऊषाकाल शुरू होता है। आदमी इस क्रम में समझा था कि दुनिया में सब कुछ अन्तर्निहित नियमों का पालन कर रहा है। अतः, इन छिपे हुए नियमों को खोजने के संघर्ष के सिलसिले में विज्ञान की कई विधाएं विकसित हुईं। लेकिन समाज के व्यवस्थित ढंग से अध्ययन का प्रयोग महान चिंतनकार कार्ल मार्क्स द्वारा सोचा-विचारा और अपनाया गया था। सामाजिक विकास में उनके शोध ने साबित किया कि वर्ग संघर्ष इतिहास के ईजन हैं। उनके शोध ने दिखाया कि दो वर्ग, सम्पत्तिधारी वर्ग और सम्पत्तिहीन वर्ग इतिहास में एक खास स्तर पर आने पर समाज में उभरे थे और जब तक वर्ग रहेंगे वर्ग संघर्ष भी रहेगा और तेज होता जाएगा और अन्ततः वर्गहीन साम्यवादी समाज की ओर ले जाएगा। सामाजिक विकास के ये वे नियम थे जिनको मार्क्स ने प्रतिपादित किया था।”

सभाध्यक्ष पार्टी की राज्य सचिवमण्डल सदस्य डॉ. के. उमा ने कहा, “किसी भी आदमी का मरना निस्संदेह दुखदायी होता है। लेकिन डॉ. शिवदास घोष की मौत को याद करना न केवल दुखदायी अनुभव है, बल्कि यह उनके क्रान्तिकारी जीवन-संघर्ष और चिंतन को कोने-कोने में फैला देने के लिए हमें प्रेरित भी करता है।”

कॉमरेड शिवदास घोष के संघर्ष के इतिहास का

जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “13 साल की उम्र में डॉ. शिवदास घोष आजादी आन्दोलन के भंवर में कूद पड़े थे और बाद में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विचारों के सम्पर्क में आये। उन्होंने अपने सहयोद्धाओं के साथ मिल कर जेल में मार्क्सवाद का अध्ययन, चर्चा-बहस और अभ्यास किया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों का बारीकी से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एम.एन. राय सहित वे सब अपनी ईमानदारी और निष्ठा-लगन के बावजूद कम्युनिस्ट बन पाने में नाकाम हुए क्योंकि वे नये किस्म का संघर्ष करने में विफल हुए। इसलिए उन्होंने भारत की सरजमीं पर सही कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) बनायी। उन्होंने डॉ. शिवदास घोष की शिक्षाओं को दोहराया जिन्होंने कहा था कि समय-समय पर जनविक्षोभ, शिकवे-शिकायत की लहर पर लहर फूट पड़ने के बावजूद जब तक इनका नेतृत्व वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की सही समझ के साथ एक सही कम्युनिस्ट पार्टी नहीं करेगी, तब तक इन जनान्दोलनों का उफान उतरता रहेगा।

उन्होंने आगे कहा, “अपने घोषित लक्ष्य पूरे करने में नोटबंदी की बड़ी भारी विफलता के बाद अब शासक बीजेपी प्रदर्शनकारी किसानों, छात्रों और अन्य तबकों के मेहनतकश लोगों के असन्तोष को दबाने के लिए मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए साम्प्रदायीकरण और भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मार डालने के काण्ड आदि दूसरे-दूसरे मुद्दों की तरफ फेरने का सहारा ले रही है। वक्त का तकाजा है कि इन सब प्रयासों के खिलाफ जोरदार आन्दोलन खड़ा किया जाये।

सभा की शुरुआत दिवंगत महान नेता की तस्वीर पर एसयूसीआई(सी) के कई नेताओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुई। इसका समापन कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं को लागू करने और वर्ग संघर्ष व जन आन्दोलनों को मजबूत करने के दृढ़ संकल्प के साथ हुआ।

श्रीनगर (उत्तराखण्ड) : उत्तराखण्ड के श्रीनगर-गढ़वाल की केदार-बद्री धर्मशाला के हाल में 5 अगस्त को महान नेता डॉ. शिवदास घोष की स्मृति सभा हुई। भारी बरसात के बावजूद इस सभा में बहुत सारे छात्र-नौजवान शामिल हुए जिनको एसयूसीआई(सी) के मध्य प्रदेश राज्य सचिव डॉ. प्रताप सामल ने संबोधित किया। डॉ. सामल ने भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन में डॉ. शिवदास घोष के चिंतन का महत्व दर्शाया।

सभा शुरू होने से पहले डीएसओ स्वयंसेवकों द्वारा क्रान्तिकारी गाने पेश किये गए। सभा का संचालन डॉ. मुकेश सेमवाल ने किया।

जयपुर (राजस्थान) : राजस्थान के जयपुर के पटेल गार्डन हाल में 13 अगस्त को सर्वहारा के महान नेता डॉ. शिवदास घोष की स्मृति सभा हुई। एसयूसीआई(सी) राजस्थान राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य डॉ. राजमल शर्मा ने सभा में आये लोगों का स्वागत किया। सभा की अध्यक्षता पार्टी की राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य डॉ. आर डी चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि एसयूसीआई(सी) के संस्थापक महासचिव डॉ. शिवदास घोष ने शोषणहीन समाज बनाने के हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अथक संघर्ष किया और भारत की धरती पर एकमात्र सही कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई(सी) बनायी। अब इसे मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है।

सभा को एसयूसीआई(सी) के हरियाणा राज्य सचिव और केन्द्रीय कमेटी सदस्य डॉ. सत्यवान ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डॉ. शिवदास घोष ने बार-बार यह समझाया था कि हमारा समाज वर्ग विभाजित है। एक तरफ बहुसंख्यक मेहनतकश लोगों का बेरहम शोषण-उत्पीड़न किया जा रहा है और शोषक मुट्ठीभर पूँजीपतियों के हाथों में बेशुमार धन-दौलत के अम्बार लग गए हैं। मजदूर वर्ग ही एकमात्र क्रान्तिकारी वर्ग है जो हर तरह के अन्याय-अत्याचार के खिलाफ संगठित होकर पूरे समाज को शोषण से छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए चाहिए पर्याप्त शक्ति के साथ क्रान्तिकारी पार्टी। भारत के क्रान्तिकारी पार्टी एसयूसीआई(सी) का



बंगलौर : सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड के. राधाकृष्ण

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ब्रिक्स ट्रेड यूनिन फोरम में एआईयूटीयूसी ने की शिरकत

24-25 जुलाई को चीन की राजधानी बीजिंग में और 26-27 जुलाई को चीन के चांगकिंग में आयोजित ब्रिक्स ट्रेड यूनिन फोरम वार्ता में एआईयूटीयूसी का प्रतिनिधित्व उपाध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्ण ने किया। इस फोरम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की ट्रेड यूनिनों से प्रतिनिधि शामिल हुए। जहां ज्यादातर वक्ताओं ने यह महसूस किया कि ट्रेड यूनिनों को विश्व बाजार में अपने-अपने बाजारों को हथियाने के लिए ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए अपने-अपने देश की सरकारों की नीतियों का समर्थन करना पड़ता है क्योंकि ब्रिक्स के पास इस समय 48 प्रतिशत विश्व बाजार है, वहीं एआईयूटीयूसी की ही लगभग एक अकेली आवाज है जो मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए पूंजीवादी भूमण्डलीकरण का विरोध करती है। एआईयूटीयूसी के विचारों को पेश करते हुए डॉ. राधाकृष्ण ने दिखाया कि रूस में समाजवाद के दुःखद पतन और समाजवादी खेमे के



बीजिंग:फोरम को सम्बोधित करते हुए डॉ. के. राधाकृष्ण

वस्तुतः ढह जाने के बाद साम्राज्यवादी-पूंजीवादी शासक, उदारीकरण, भूमण्डलीकरण, निजीकरण की धिनौनी नीति के हिस्से के तौर पर सभी श्रम कानूनों को बदलते जा रहे हैं जो उनके मतानुसार अधिकतम मुनाफा कमाने में बाधा पैदा करते हैं। भारत में 8 घण्टे के कार्य दिवस जैसे बड़े कष्टों से अर्जित अधिकार

छीने जा रहे हैं। न्यूनतम वेतन कानून, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, ईएसआई और साथ ही साथ समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धान्त की भी धज्जियां उठाई जा रही हैं। स्थायी रोजगार की धारणा की बजाए ठेका प्रथा के तहत मजदूरी और अस्थायी रोजगार की धारणा लायी जा रही है। यहां तक कि वेतन की जगह मानदेय भते और प्रोत्साहन राशि आदि दिए जा रहे हैं। संक्षेप में मजदूरों की छटनी करके सड़कों पर फेंका जा रहा है। इसके मद्देनजर 'रोजगार का लचीलापन' कहने का मायने है मजदूरों के हितों की बलि चढ़ाकर मालिकों के हितों को बुलन्द करना। एआईयूटीयूसी इसके सख्त खिलाफ है। डॉ. राधाकृष्ण ने सभी ट्रेड यूनिनों, खासकर ब्रिक्स देशों से जो यहां आकर जुटी हैं, अपील की कि अपने-अपने देशों में मालिकों के निर्मम शोषण के खिलाफ और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों और जोरदार आन्दोलन गठित करें।

सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ विधानसभा के समक्ष हुए प्रदर्शन



रांची (झारखंड) : झारखण्ड राज्य में सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ 8 अगस्त को विधानसभा के समक्ष हुए प्रदर्शन में एआईकेकेएमएस कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। भूमि अधिकार आन्दोलन के बैनर तले हजारों किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाएं जुटी। प्रदर्शन के बाद विधानसभा के गेट पर हुई सभा को सम्बोधित करते हुए एआईकेकेएमएस के राज्य सचिव डॉ. विमल जाना ने कहा कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जबरन जमीन छीनने वाली नीति के तहत आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर पूंजीपतियों को देने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर रही है। यह किसान-विरोधी तथा आदिवासी-विरोधी नीति है। इसका हमारा संगठन झारखण्ड के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी विरोध करता है। साथ ही भूमि अधिकार आन्दोलन के साथ कदम से कदम मिला कर आन्दोलन में शामिल है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के खिलाफ जोरदार और दीर्घकालिक आन्दोलन खड़ा करने में लगा हुआ है। सभा में इनके अलावा एआईकेकेएमएस के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड रामलाल महतो, सीताराम टुडू, लिली दास, धीरेन भक्त, सुशांतों सरकार, झरीलाल महतो, भुजंग मछुआ, गौतम महतो, सुलोचना माछी आदि भी मौजूद थे।

5 अगस्त ...

(पृष्ठ 4 का शेष)



जयपुर: सभा को संबोधित करते हुए डॉ. सत्यवान

निर्माण डॉ. शिवदास घोष कर गए हैं। उन्होंने इसे मजबूत करने के लिए सभी लोगों का आह्वान किया और जनता

श्रीमती मेधा पाटकर की जायज मांगों को मानकर उनका अनशन समाप्त कराने के लिए तुरन्त सरकारी हस्तपेक्ष की मांग करते हुए प्रधान मंत्री को भेजा टेलिग्राम

8 अगस्त, 2017

सेवा में

माननीय प्रधान मंत्री

भारत सरकार

गुजरात में सरदार सरोवर के गेट बन्द होते ही 176 गांवों के 40,000 गरीब लोग डूब की जद में आ जाएंगे। उनके उचित पुनर्स्थापन और पुनर्वास की मांग को लेकर जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेता मेधा पाटकर 12 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। जहां यह अपेक्षा थी कि केन्द्र और मध्य प्रदेश राज्य की सरकारें मेधा पाटकर की जायज मांगों को मानते हुए यह सुनिश्चित करेंगी कि वे अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दें। इसकी बजाए मध्य प्रदेश सरकार ने अति गैर जनतांत्रिक ढंग से और

बर्बरता से उन पर और उनके सहयोगियों पर पुलिस का धावा बोल दिया, अनशन स्थल को तहस-नहस कर दिया, बेरहमी से लाठीचार्ज किया जिससे पीड़ित लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। हम इस घटना की पुरजोर निन्दा करते हैं, केन्द्र सरकार से तुरन्त हस्तपेक्ष का आग्रह करते हैं और मांग करते हैं कि उनकी मांगें मानी जाएं, श्रीमती मेधा पाटकर सहित सभी पीड़ितों को उचित मेडिकल उपचार का खर्च सरकार वहने करे, जो क्षति हुई है उसके लिए दनको उचित मुआवजा दिया जाए और न्याय संगत उद्देश्य के लिए एक शान्तिपूर्ण जनवादी आन्दोलन पर इस तरह का पाशविक हमला चलाने के दोषियों को सख्त सजा दी जाए।

भवदीय

प्रभाष घोष

महासचिव, एसयूसीआई (सी)

पूर्ण पुनर्वास किये बिना बांध के गेट बंद किये जाने के खिलाफ दिल्ली स्थित म.प्र. भवन, के समक्ष प्रदर्शन

नई दिल्ली : 27 जुलाई से अनशन पर बैठी नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेत्री मेधा पाटकर को अनशन स्थल से उठाने और पुलिस द्वारा हस्पताल में रखे जाने, किसी से मिलने न देने और पण्डाल उखाड़ फेंकने आदि दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ नर्मदा बचाओ आन्दोलन (एनबीए) द्वारा 8 अगस्त को नई दिल्ली स्थित म.प्र. भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में स्वराज इण्डिया के अध्यक्ष योगेन्द्र यादव, किसान सभा के डॉ. हनान मौल्ला और ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. सत्यवान भी शामिल थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पुनर्वास का पर्याप्त प्रबंध किये बिना ही म.प्र. में नर्मदा बांध के गेट बंद किये जाने से डूब क्षेत्र के लोगों के लिए जान-माल का खतरा पैदा



दिल्ली : म.प्र. भवन पर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए डॉ. सत्यवान

हो गया है। जो टीन शैड सरकार द्वारा लोगों को बसाने के लिए बनाये गए हैं, वे इन्सानों के रहने लायक नहीं हैं। मंदसौर गोलीकाण्ड के बाद उभरते हुए किसान आन्दोलन को कुचलने के लिए बीजेपी की म.प्र. सरकार की दमनकारी नीतियों की भी उन्होंने कड़े शब्दों में निन्दा की।

की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जोरदार जन आन्दोलन गठित करने के डॉ. शिवदास घोष के संदेश को हर गांव-शहर में ले जाने का आह्वान किया।

एसयूसीआई(सी) की प.बं. राज्य कमेटी की सदस्य डॉ. प्रतिभा नायक भी सभा में मौजूद थीं।

जौनपुर (उ.प्र.) : डॉ. शिवदास घोष का 41वां स्मृति दिवस 6 अगस्त को सलतनत बहादुर इण्टर कॉलेज बदलापुर, जौनपुर (उ.प्र.) में सम्मानपूर्वक मनाया गया। इसके पहले बदलापुर में सब्जी मण्डी स्थित पार्टी के जिला कार्यालय से सैकड़ों लोगों का एक शानदार जुलूस निकाला गया। झण्डे व बैनर से सुसज्जित जुलूस के आगे-आगे लाल झण्डा लिए कॉमसोमोल संगठन के सदस्य चल रहे थे। कार्यक्रम में जौनपुर सुल्तानपुर जिला के पार्टी समर्थकों, कामरेडों व आम नागरिकों

ने भागीदारी की।

स्मृति सभा की अध्यक्षता जगन्नाथ वर्मा (कार्यालय सचिव, एसयूसीआई (सी) राज्य कमेटी उ.प्र.) व संचालन डॉ. मिथिलेश कुमार मौर्य ने किया।

सभा में मुख्य वक्ता पार्टी के उ.प्र. राज्य सचिवमण्डल सदस्य डॉ. स्वप्न चटर्जी ने डॉ. शिवदास घोष के चिंतन को जन-जन तक ले जाने की कार्यकर्ताओं से अपील की। पार्टी के उ.प्र. राज्य सचिव डॉ. बी.एन. सिंह ने वर्तमान संकटग्रस्त हालातों में कॉमरेडों के फर्ज और कार्य पर केन्द्रित चर्चा रखी। इसके अलावा सभा को डॉ. हीरालाल मौर्य, जयनारायण मौर्य, प्रमोद कुमार, शुक्ल, महेन्द्र कुमार मौर्य और सुल्तानपुर जिला सचिव डॉ. जयप्रकाश मौर्य ने सम्बोधित किया।

मुंशी प्रेमचंद जयंती मनायी

देवा भर में हिन्दी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचन्द की जयन्ती सम्मानपूर्वक मनायी गयी। सभी जगह कार्यक्रम के प्रारम्भ में उपस्थित लोगो ने मुंशी प्रेमचन्द की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किये।

मुगलसराय:- 30 जुलाई को एआईडीवाईओ के बैनर तले मुगलसराय, चन्दौली के धारना छित्तमपुर गांव में प्रेमचन्द की जयन्ती कार्यक्रम का संचालन कॉ. संजय ने किया। अध्यक्षता कॉ. मोहन राय ने की। संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष कॉ. कमलेश मौर्य ने मुंशी प्रेमचन्द के जीवन-संघर्ष, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में भी मुंशी प्रेमचन्द के विचार प्रासंगिक हैं। कुंज बिहारी मिश्र ने कहा कि मुंशीजी की कथनी और करनी में अन्तर नहीं था। हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। इस अवसर पर राकेश, प्रताप पासवान, संजय महतो, संजय गुप्ता, विनोद कुमार, आयुश राय आदि लोग उपस्थित थे।

वाराणसी:- 31 जुलाई को एआईडीवाईओ के बैनर तले श्रीरामकृष्ण विद्या मंदिर इ.का. सिद्धगिरिबाग वाराणसी में मुंशी प्रेमचन्द की जयन्ती पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक श्री सुरेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मुंशी प्रेमचन्द की कहानियों के पात्र आज भी हमारे आस-पास जीवन्त मिल जायेंगे। आज भी होरी, धानिया, घीसू, माधाव उसी परिस्थिति में जी रहे जैसे अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन एवं सामन्ती व्यवस्था में। आज भी किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ एवं कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर रहा है। जातिवादी एवं साम्प्रदायिक ताकतें उसी तरह से आज भी समाज पर हावी हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें मुंशी प्रेमचन्द के साहित्य एवं विचारों से प्रेरणा लेकर इन समस्याओं के खात्मे के लिए आगे आना चाहिए। सभा को संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष कॉ. कमलेश मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि मुंशी प्रेमचन्द की कहानी 'आहुति' की नायिका रूक्मिणी कहती है कि यदि स्वराज के आने पर सम्पत्ति का यही प्रभुत्व बना रहे एवं पढ़ा-लिखा समाज यूं ही स्वार्थान्ध बना रहे तो ऐसे स्वराज का न आना ही अच्छा। मुंशीजी ने कहा कि साम्प्रदायिकता हमेशा संस्कृति की खाल ओढ़कर आती है। आज जिस तरह से पैसा-पूजा की भावना तेजी से बढ़ रही है एवं पढ़ा-लिखा समाज खुदगर्ज एवं आत्मकेन्द्रित होता जा रहा है और बीजेपी सरकार संस्कृति एवं राष्ट्रहित के नाम पर नंगा नाच कर रही है, उनकी कही गयी बातें और भी प्रासंगिक हो गयी हैं। अतः हम मुंशीजी से सीख लेकर अपना फर्ज निभाएं और बेरोजगारी, अपसंस्कृति, नशाखोरी, साम्प्रदायिकता एवं महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ जोरदार युवा आन्दोलन संगठित करें, तभी हम समाज के साथ-साथ अपने को भी बचा पायेंगे अन्यथा नहीं।

दिल्ली: प्रेमचन्द जयंती पर एआईडीएसओ, दिल्ली राज्य कमिटी की ओर से गुलाबी बाग-किशनगंज, दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर, नांगलोई में 30 जुलाई को व मुकुंदपुर में 31 जुलाई को विभिन्न कार्यक्रम किये गये। गुलाबी बाग-किशनगंज इलाके में कार्यक्रम का संचालन ए.आई.डी.एस.ओ. दिल्ली राज्य कमिटी सदस्य व स्थानीय कमिटी के अध्यक्ष कॉ. श्रीराम सहनी ने किया। चार्ली चैपलिन की फिल्म 'मॉडर्न टाइम्स' दिखाई गई व मुंशी प्रेमचन्द के जीवन संघर्ष पर परिचर्चा आयोजित की गई। मुख्य वक्ता प्रो नरेन्द्र शर्मा ने वक्तव्य रखा। नांगलोई इकाई के द्वारा 'कहानी पाठन' प्रतियोगिता का संचालन एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य कमिटी सदस्य व नांगलोई इकाई की अध्यक्ष कॉ. सुमन ने किया। सभा को प्रिंसिपल श्रीमती शारदा दीक्षित व एसयूसीआई (सी) के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमिटी सदस्य कॉ. रमेश पाराशर ने संबोधित किया। छात्रों ने 'अंधेर नगरी' नामक एक नाटक भी प्रस्तुत किया। दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर इलाके में भी 'कहानी पाठन' प्रतियोगिता आयोजित की गई। संचालन ए.आई.डी.एस.ओ. कॉ. अशरफ अली ने किया। सभा का संबोधन ए.आई.डी.एस.ओ. दिल्ली राज्य सचिव कॉ. श्रेया सिंह सहित शिक्षकों ने किया। बुराडी इकाई द्वारा मुकुंदपुर इलाके में फिल्म 'बूढ़ी काकी' दिखाई गई व प्रेमचन्द की जीवन संघर्ष पर चर्चा की गई। एआईडीएसओ दिल्ली राज्य सचिव कॉ. श्रेया सिंह ने अपना वक्तव्य रखा।

चण्डीगढ़ की लड़की से छेड़छाड़ व अपहरण की कोशिश करने वालों को कड़ी सजा देने की उठी आवाज

भिवानी () :

4 अगस्त की रात को चण्डीगढ़ में कथित रूप से एक लड़की के साथ छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश करने वाले बीजेपी के हरियाणा राज्य अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला व उसके दोस्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को जोरदार ढंग से उठाते हुए एआईडीवाईओ और ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन के संयुक्त बैनर तले नौजवानों और महिलाओं ने 11 अगस्त को भिवानी शहर में विरोध प्रदर्शन किया और स्थानीय हांसी गेट पर हरियाणा की बीजेपी सरकार का पुतला फूँका। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में युवक व महिलाएं दिनाद गेट स्थित चेताराम प्रजापति धर्मशाला में एकत्रित हुए। वहां से जुलूस सराय चौपटा-घण्टाघर होते हुए हांसी गेट पहुंचा।

ए.आई.डी.वाई.ओ. के जिला सचिव सन्दीप मेहरा और ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की जिला सचिव श्रीमती बिमला जांगड़ा ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह घटना न केवल एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा की गारण्टी की पोल खोल देती है बल्कि बीजेपी की असल महिला-विरोधी मानसिकता का भी पर्दाफाश कर देती है। इस घटना से भाजपा का चाल-चरित्र-चेहरा जनता के सामने आ गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा की राजधानी में ही महिलाओं की सुरक्षा का हाल यह है तो बाकि प्रदेशों में क्या होगा? हर रोज महिलाओं के अपहरण, बलात्कार और फिर निर्मम हत्या कर फेंक देने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इसके चलते, आज प्रदेश में नन्ही बच्ची से लेकर बुरजुग महिला तक, कोई भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। सरकार इन्टरनेट, टीवी, विज्ञापनों आदि माध्यमों से अश्लीलता को बढ़ावा दे रही है। शराबखोरी-नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है। नतीजतन महिलाओं पर जघन्य अपराध बढ़े हैं। इनकी रोकथाम के लिए सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। इससे 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' और 'ऑपरेशन दुर्गा' जैसे नारे थोथे व बेजान साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़िता को उचित न्याय नहीं मिला जाता हम आन्दोलन करते रहेंगे। आने वाले समय में इस मुद्दे को राज्य स्तर तक उठायेंगे ताकि सरकार पर दबाव बनाकर कर महिलाओं की इज्जत-आबरू की रक्षा व जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और चण्डीगढ़ में महिला से छेड़छाड़ व अपहरण की कोशिश करने वालों को उदाहरणमूलक सजा दिलायी जा सके।

पुतला दहन कार्यक्रम में छात्र संगठन ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. भी शामिल रहा। कार्यक्रम में विकास, पूजा, राजेश, पवन, रोहित, मीना, सोनू, कमल, जंगवीर, पूनम, मुनेश, विशाल, संजय, कविता और कृष्ण विशेष रूप से शामिल रहे।

रोहतक (हरियाणा) : 11 अगस्त को क्रान्तिकारी छात्र संगठन ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. की ओर से चण्डीगढ़ में भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला व उसके दोस्त द्वारा आई.ए.



भिवानी

एस. अधिकारी की बेटी के अपहरण का प्रयास करने के मामले की निष्पक्ष जांच कराने व दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर राज्यपाल हरियाणा सरकार को उपायुक्त रोहतक के मार्फत ज्ञापन सौंपा।



रोहतक

संगठन ने मांग की कि :

1. वर्णिका घटना के दोषियों को बचाने के लिए भाजपा सरकार व चण्डीगढ़ प्रशासन दखलन्दाजी बन्द करे।
2. इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए व उनको बचाने में शामिल सभी लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाही की जाए। इसके लिए तत्काल कदम उठाये जाएं।
3. महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जाएं।
4. ऐसी घटनाओं पर कारगर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाये जाएं।

सोनीपत (हरियाणा) : 14 अगस्त को महलाना चौक पर एआईडीएसओ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मैडिकल कालेज में सरकार की लापरवाही की वजह से हुई 70 बच्चों की दर्दनाक मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसके विरोध में यू.पी. सरकार का पुतला दहन किया।

का. राजेश कुमार ने कहा कि 'अच्छे दिन' आने का सपना दिखाने वाले केन्द्र व राज्य में शासन में बैठी बीजेपी सरकार छोटे-छोटे नवजात शिशुओं तक की जान नहीं बचा रही है तो देश की जनता की मूलभूत समस्याओं का ये क्या समाधान करेगी। यह घटना घोर निन्दनीय है। लेकिन बीजेपी के नेताओं व मंत्रियों द्वारा दिए गए तरह-तरह के बयानों द्वारा परोक्ष रूप से दोषियों को बचाना और भी शर्मनाक हैं।



सोनीपत : बीजेपी सरकार का पुतला फूँकते हुए छात्र

गोरखपुर हस्पताल में बच्चों की हुई दर्दनाक मौत के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग पर अहमदाबाद, बड़ोदरा व सूरत में एमएसएस का रोष प्रदर्शन



अहमदाबाद

बड़ोदरा

सूरत

मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

द्वारा चलाई जा रही कार्पोरेट परस्त राष्ट्र-विरोधी और जनविरोधी नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हो रही कामगार जनता की आजीविका पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई।

राष्ट्रीय सम्मेलन ने बीजेपी की मोदी सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों को उलटवाने के लिए मिल कर लड़ने का फैसला किया। सम्मेलन में जोरदार मजदूर आन्दोलन खड़ा करके 12 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए सर्वसम्मति से ये कार्यक्रम लिये गए :

1. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उठाई गई मांगों के संदर्भ में संयुक्त आन्दोलनों को खड़ा करने और आन्दोलनों को तेज करने की दिशा में काम करना।

2. राष्ट्र स्तरीय लामबन्दी की तैयारी के लिए ब्लॉक/जिला/केन्द्रीय/राज्य सरकार के औद्योगिक केन्द्रों पर भीषण प्रचार, लामबन्दी और सम्मेलन संगठित किए जाएं।

3. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीन दिवसीय लगातार विशाल धरना संगठित किया जाएगा जिसमें हर रोज देशभर के लाखों मजदूर भागीदारी करेंगे।

4. राष्ट्रीय सम्मेलन विभिन्न सेक्टरों में कार्यरत देशभर की मजदूर जनता को आह्वान करता है कि संबंधताओं से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाएं।

राष्ट्रीय सम्मेलन कामगार जनता से आह्वान करता है कि सरकार की जन विरोधी, राष्ट्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल के लिए तैयार हों।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में इंटक, एटक, एच.एम. एस., सीटू, ए.आई.यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., सेवा, एक्टू, यू.टी.यू.सी., एल.पी.एफ. राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन शामिल रही।

12 सूत्रीय मांगें

1. जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के सार्वजनिकीकरण द्वारा मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के तत्काल उपाय किए जायें।

2. रोजगार सृजन के ठोस उपायों से बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जाए।

3. सभी मूलभूत श्रम कानूनों को किसी अपवाद या छूट के बगैर सख्ती से लागू किया जाए और श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कड़े दण्डात्मक कदम उठाये जाएं।

4. सभी मजदूरों को सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा दी जाए।

5. न्यूनतम वेतन कम-से-कम इंडेक्सेशन के प्रावधान के साथ 18000 रुपये प्रति माह हो।

6. सभी कामगार आबादी के लिए सुनिश्चित रूप से बढ़ाई गई पेंशन 3000 रुपये प्रति माह से कम न हो।

7. केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) के विनिवेशिकरण और रणनीतिक बिक्री को बन्द करो।

8. सालभर होने वाले कामों में अनुबंधीकरण/ठेकेदारी बन्द हो और समान काम के लिए नियमित मजदूर की तरह अनुबंध और ठेका मजदूरों को भी समान वेतन का भुगतान, लाभ मिले।

9. बोनस और प्रोविडेंट फण्ड के भुगतान और पात्रता पर लगी सभी सीमाबन्धियों को हटाया जाए तथा ग्रेट्यूटि की राशि बढ़ाई जाए।

10. ट्रेड यूनियनों द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र जमा किए जाने के 45 दिनों के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य रूप से हो और आईएलओ कन्वेंशन सी 87 और सी 98 का तत्काल अनुसमर्थन हो।

11. श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों को रद्द किया जाये।

12. रेलवे, इश्योरेंस और डिफेंस में एफ.डी.आई. (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) बन्द किया जाये।

जिनेवा में आईएलसी के 106वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एआईयूटीयूसी ने की शिरकत

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जिनेवा में 5 से 16 जून, 2017 तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आई.एल.सी.) का 106वां सत्र आयोजित किया गया। सम्मेलन में 187 देशों से मजदूरों, मालिकों और सरकारी समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9074 प्रतिनिधियों और परामर्शदाताओं ने हिस्सा लिया। एआईयूटीयूसी के अखिल भारतीय सचिव मण्डल सदस्य कॉमरेड शंकरदास गुप्ता ने सम्मेलन में संगठन का प्रतिनिधित्व किया।

सम्मेलन का मंतव्य था कि गहराते चौतरफा पूँजीवादी संकट का सारा बोझ पूँजीपति मालिकों द्वारा मेहनतकश लोगों के कन्धों पर लादा जा रहा है जिसके चलते पूरी दुनिया में मेहनतकशों का जीवन तबाह होता जा रहा है। सभी पूँजीवादी देशों में आई.एल.ओ. मानकों का उल्लंघन हो रहा है। यह सभी के संज्ञान में लाया गया कि भारत सरकार ने आई.एल.ओ. का सदस्य राष्ट्र होने के नाते आई.एल.ओ. कन्वेंशन नं. 81 का अनुमोदन 1949 में किया था। फिर भी, इसने लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947 (नं. 81) का घोर उल्लंघन करते हुए तथा कथित 'इंस्पेक्टर राज' को खत्म करने के अपने उद्देश्य की खातिर लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम को मौलिक रूप से संशोधित कर दिया है। बालश्रम, जबरी श्रम (बेगार), काम के घण्टों, कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य तथा विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) के मामलों में भारत में श्रम कानूनों का व्यापक उल्लंघन होता है। 'फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एण्ड राइट एट वर्क' पर लगातार दूसरी बार होने वाली चर्चा में मुख्य फोकस, अब 20 करोड़ तक जा पहुंची

भूमण्डलीय बेरोजगारी, बढ़ती मंदी, काम के बदतरीन हालात जिससे दुनियाभर में 150 करोड़ कामगार प्रभावित हैं, बढ़ती गैरबराबरी, वेतन जाम में हो रही खतरनाक बढ़ती और रोजगार की असुरक्षा, 6.53 करोड़ मेहनतकश लोगों का जबरन विस्थापन और दुनिया की 700 करोड़ आबादी में से 150 करोड़ लोगों के भयंकर रूप से कंगाल होने पर था। कामेटी का कहना था कि तमाम राष्ट्रीय सरकारों को त्रिपक्षीय बातचीत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि 'आई.एल.ओ., डिक्लोरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एण्ड राइट एट वर्क, 1998' का लागू होना सुनिश्चित किया जा सके।

कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने विभिन्न देशों से आये श्रमिक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इनकी सीमाबद्धताओं के बावजूद आई.एल.ओ. के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए पूँजीवादी गुलामी के जुए से मुक्ति की महत्वपूर्ण जरूरत को मजदूर वर्ग को समझाए ताकि विश्व पूँजीवाद-साम्राज्यवाद के बढ़ते शोषण और बर्बरता के खिलाफ पूरी दुनिया में संयुक्त, सतत और शक्तिशाली आन्दोलन विकसित किये जा सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ ऐसे सशक्त सचेत संगठित आन्दोलन ही शोषणमूलक पूँजीवाद व्यवस्था का खात्मा करके एक नये समाज का आगाज कर सकते हैं जिसे समाजवाद कहा जाता है जो पूँजी के शोषण दमन से पूरी तरह मुक्त होगा जैसा कि सोवियत रूस में महान नवम्बर समाजवादी क्रान्ति ने करके दिखाया था।

किसानों के कर्ज माफ करने, फसलों के लाभकारी दाम देने आदि मांगों को लेकर रोहतक मण्डल के किसानों का प्रदर्शन

रोहतक (हरियाणा) : किसानों का कर्ज खत्म करने और फसलों के लाभकारी दाम देने की दो प्रमुख मांगों को लेकर देशभर में किसानों ने विभिन्न जगह जोरदार प्रदर्शन किये, अनेक स्थानों पर गिरफ्तारियां भी दी गईं। इसी कड़ी में ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन और ऑल इण्डिया किसान सभा दो किसान संगठनों ने 9 अगस्त को रोहतक के मण्डल आयुक्त कार्यालय पर मिलकर साझा प्रदर्शन किया।

दोनों संगठनों के कार्यकर्ता पहले सेक्टर-1 के देवीलाल पार्क में इकट्ठा हुए। वहां ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के प्रदेश सचिव कामरेड जयकरण माण्डौठी व किसान सभा के जयभगवान बेनीवाल ने सम्बोधित किया। वहां से विरोध जुलूस जब दिल्ली बाईपास से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की ओर मुड़ा तो पुलिस ने अवरोध लगाकर आगे जाने से रोक दिया। कई देर तक कार्यकर्ताओं ने पुलिस की इस नाजायज कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और आयुक्त कार्यालय तक जाने के लिए दबाव बनाया। वहां सोनीपत से ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेता रामकरण और किसान सभा के फूलचन्द श्योकन्द ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया। यह देखकर कि आन्दोलनकारी हटने वाले नहीं हैं, आखिर जिला प्रशासन ने प्रदर्शन को आयुक्त कार्यालय की बजाय लघुसचिवालय तक जाने की पेशकश की। जुलूस पूरे शहर के बीचों-बीच महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, जाट कॉलेज, पावर हाऊस, मेडिकल मोड़, माडल टाऊन, मानसरोवर पार्क होते हुए लघु सचिवालय पहुंचा।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कर्ज मुक्ति व फसलों के लाभकारी दाम देने की मांगों के ज्ञापन एस.डी.एम. को दिये गये। वहां प्रदर्शनकारियों को



रोहतक : मण्डल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन में शामिल किसान

ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान व किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ने सम्बोधित किया।

कॉमरेड सत्यवान ने नर्मदा बचाओ आन्दोलन की सुप्रसिद्ध नेत्री मेधा पाटकर को नाजायज हिरासत में लेने का कड़ा विरोध किया जो पिछली 27 जुलाई से चिखल्दा (बडवानी, मध्य प्रदेश) में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी थी। उनके साथ आन्दोलनकारी 11 महिलाएं भी अनशन पर बैठी थी, वहां पुलिस ने भीषण लाठीचार्ज करके पण्डाल को उखाड़ फेंक दिया और मेधा पाटकर को नाजायज हिरासत में लेकर इन्दौर अस्पताल में दाखिल करा दिया परन्तु किसी को भी मिलने तक की इजाजत नहीं दी गयी।

सरकार की क्रूरता और निष्ठूरता बाढ़ पीड़ितों को धकेल रही है दुर्दशा व जोखिम की ओर बाढ़ से बचाव, राहत और उचित मुआवजे की एसयूसीआई (सी) ने की मांग

15 अगस्त, 2017 को एसयूसीआई(सी) के महासचिव का. प्रभाष घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया:

आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल में हर बीते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही बाढ़ की स्थिति से हम गहरी चिंता और आशंका में हैं। पहले ही एक बड़ी संख्या में लोग जान गवां चुके हैं, बहुत से घर और सम्पत्तियां नष्ट हो गईं और अच्छी खासी संख्या में पशु और अन्य घरेलू जानवर बह गये हैं। लेकिन केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव और राहत के लिए मुश्किल से ही कोई कदम उठाया है। केन्द्र और राज्य सरकारों की क्रूरता और निष्ठूरता अभागे बाढ़ पीड़ितों को दुर्दशा और जोखिम में धकेल रही है।

यह सच है कि प्राकृतिक आपदा, बारिश का कम या ज्यादा होना सरकार के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन विज्ञान की शानदार प्रगति और बहु-आयामी तकनीकी विकास के इस आधुनिक युग में प्राकृतिक प्रकोपों, से होने वाली क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है और लोगों की तकलीफों को बहुत दूर तक घटाया जा सकता है।

पहली बात तो यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारें अपने बजटों का एक बड़ा हिस्सा मिल्ट्री, पुलिस और

प्रशासन पर खर्च करती है। सिंचाई, नदियों, बांधों, नहरों और तालाबों की गाढ़ निकालने के साथ-साथ उथली भूमियों के नवीनीकरण और नये जलाशय तैयार करने के लिए कहत ही कम बजटीय आवंटन किया जाता है। अगर इन बेहद जरूरी कामों पर पर्याप्त खर्च किया जाता तो रोजगार पैदा किये जा सकते थे और साथ ही साथ संचित पानी का इस्तेमाल सूखे और बरसात की कमी के दौरान खेती के लिए किसानों द्वारा किया जा सकता था। न तो बारिश या बाढ़ के पानी की निकासी की वस्तुतः कोई व्यवस्था है, न ही सिवरेज सिस्टम की कोई उचित व्यवस्था है। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों की तरफ से बरती जाने वाली कोताही ही बाढ़ ग्रसित लाखों लोगों की दुख तकलीफों के साथ-साथ सम्पत्ति के भयंकर नुकसान के लिए जिम्मेदार है। आपदा प्रबन्धन व्यवस्था का सिर्फ साइन बोर्ड ही लटक रहा है। प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित क्षेत्रों में इस सरकारी विभाग का कोई भी कारिन्दा नजर नहीं आता है। इसलिए सरकार की तरफ से बचाव कार्य मुश्किल से ही दिखाई देता है। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को मिलट्री, पुलिस और प्रशासनिक बल लगा कर युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य चलाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकारों द्वारा जो भी थोड़ी बहुत राहत वितरित की जा रही है उसमें ढीलेपन, स्वजन-पक्षपात

और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन हालात में हम मांग करते हैं :

1. बारिश की कमी या बहुतायत से निपटने के लिए फौरी और लम्बी अवधि की दोनों योजनायें विशेषज्ञों की बहुमुल्य राय लेकर लागू की जायें।
2. राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सर्वदलीय कमेटियां बनाकर उचित तरीके से राहत और बचाव कार्य संचालित किये जाएं।
3. केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों में तुरन्त आदमी और सामान की पर्याप्त मदद भेजी जाये।
4. बाढ़ पीड़ितों को उचित मेडिकल इलाज मुहैया कराने के लिए सरकारी के साथ-साथ निजी मेडिकल टीमों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरन्त भेजी जायें।
5. बाढ़ पीड़ितों के इलाज का सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए और
6. बाढ़ प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, बाढ़ से तबाह हुए घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जाये, बाढ़ पीड़ितों के कृषि ऋण सहित सारे कर्जे माफ किये जायें और उन्हें खेती बाड़ी के लिए नई वित्तीय सहायता प्रदान की जाये, बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए, प्रभावित छात्रों की स्कूल और अन्य फीसें माफ की जायें और किताबें और कापियां मुफ्त प्रदान की जायें।

देश भर में किया गया 'इण्डिया मार्च फॉर साइंस'

देश के विभिन्न भागों में 9 मार्च को एक नये तरह का जुलूस 'इण्डिया मार्च फॉर साइंस' आयोजित किया। विज्ञान की प्राणसत्ता को बचाने के लिए प्रयोगशाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ कर हजारों जाने-माने वैज्ञानिक, शोधकर्ता, प्रोफेसर, छात्र सड़कों पर उतरे। देश के जिन 40 बड़े-बड़े शहरों में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ उनमें प्रमुख थे दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, अगरतला, पटना, भागलपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, त्रिवेन्द्रम, बेल्लारी, गुलबर्गा, मैसूर, देवेनागरे, तुमकुर, धारवाड़, चित्रदुर्ग, चण्डीगढ़ आदि।

अन्य बातों के अलावा यह मांग की गई कि अवैज्ञानिक, रूढ़िवादी विचारों के प्रचार-प्रसार पर तुरन्त रोक लगायी जाए और यह आश्वासन दिया जाए कि देश की शिक्षा व्यवस्था केवल वैज्ञानिक प्रमाणों

द्वारा समर्थित विचारों की ही शिक्षा प्रदान करे। सरकार से यह भी मांग की गयी कि वैज्ञानिक रिसर्च के लिए जी.डी.पी. का 3 प्रतिशत और आम शिक्षा के लिए भी 10 प्रतिशत आवंटित किया जाए।

गत 22 अप्रैल को वसुन्धरा दिवस पर दुनिया के

100 देशों के 600 से भी ज्यादा शहरों में इसी तरह के जुलूस हुए थे। एक समय पूंजीवाद द्वारा विज्ञान की पुष्टपोषकता किये जाने पर भी आज सभी पूंजीवादी देशों में विज्ञान बेहद अवहेलना का शिकार है। क्यों है इस पर भी खोज करनी की जरूरी है।



चित्रदुर्ग, कर्नाटक



चण्डीगढ़



दिल्ली



इलाहाबाद



हैदराबाद

गोरखपुर हस्पताल में बच्चों की दर्दनाक मौत पर निकाला मौन जुलूस, दोषियों को सजा देने की उठाई मांग

जौनपुर (उ.प्र.) : बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में प्रशासनिक लापरवाही के चलते आक्सीजन सप्लाय न होने से हुई 70 मासूम बच्चों की मौत के विरोध में 16 अगस्त को एसयूसीआई(सी) की जौनपुर जिला कमेटी के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाला गया।

सब्जी मण्डी के सामने स्थित पार्टी कार्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस की शकल में बदलापुर नगर का भ्रमण करते हुए इन्दिरा चौक पर पहुंच कर मृत मासूम बच्चों की याद में बनी वेदी पर श्रद्धासुमन अर्पित किये।

श्रद्धांजलि देने वालों में पार्टी के जिला सचिव कां. रविशंकर मोर्य, कार्यालय सचिव कां. हीरालाल गुप्ता,

कोषाध्यक्ष कां. जयनारायण मोर्य के अलावा अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री कां. राजेन्द्र प्रसाद तिवारी एडवोकेट, कां. इन्दु कुमार शुक्ल एडवोकेट, मिथिलेश मोर्य, दिलीप खरवार, कां प्रमोद कुमार शुक्ल एडवोकेट, कां. श्रीपति सिंह, कां. प्रवीण शुक्ल, कां. लालता प्रसाद आदि रहे।

पार्टी ने मांग की कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के मृत बच्चों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाये और इस घटना की न्यायिक जांच करा कर दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाये और सरकारी हस्पतालों में व्याप्त दुर्दशा तत्काल दूर की जाये।

